दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के मामले

468. श्री ईश दत्त यादव:
श्री नागमणि:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से कितनी शिकायतों का निपटान किया गया तथा शिकायतें और आगे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई हैं;

(ग) इसमें दोषी पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटस्वरलु): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उनके सतर्कता विभाग में शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:—

1993-94	1994-95	1995-96
1053	926	899

उन शिकायतों की संख्या, जिन्हेंने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद सतर्कता संबंधी कारण न पाये जाने की वजह से बंद कर दिया गया:—

865	644	360

उन शिकायतों की संख्या जिनकी सतर्कता विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है:—

188	280	539

जांच हेतु सी बी आई को भेजी गई शिकायतों की संख्या:—

—	3*	1*

(ग) दोषी पाये गये कर्मचारियों की संख्या:—

94*	97*	144*

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या जिन पर असाधारण शास्ति लगाई गई है:—

23*	11*	17*

उन कर्मचारियों की संख्या जिस पर साधारण शास्ति लगाई गई है:—

71*	86*	127*

*इन आंकड़ों में पहले के वर्षों की शिकायतें भी शामिल है।

Availability of Drinking Water in Rural Areas

469. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what are the details of steps taken by Government to make drinking water availability in niral areas in different States of the country under the Minimum Needs Project; and

(b) the targets fixed for this purpose/

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHAN-DRADEO PRASAD VARMA):

(a) Safe drinking water facilities are be-ing provided to "Not Covered" and "Partially Covered" habitation under the Normal Plan Progranune of Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission • and State Sector MNP. For this purpose, the States/Union Territories have been requested to formulate and implement the action plans. Necessary funds are being provided to the States/UTs under Accelerated Rural Water Supply Programme in addition to their State Plan Funds.

(b) the target fixed for 1996-97 is to cover 8698S habitations with safe drinking water facilities.